

आज

बेबाक

1964 में आई फिल्म मेरा साया का एक गाना बेहद मशहूर हुआ था- झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में....। वह झुमका अब मिल गया है। बरेली के एक तिराहे में पूरे दो किटल का झुमका लगा दिया गया है। अब आगरा वालों ने यह गाना - आगरे से घाघरा मंगादे मेरे सैया, पकड़ फिर बैया.... बजाया बंद कर दिया है। उन्हे डर है कि आगरा प्रशासन भी किसी चौराहे पर बड़ा सा घाघरा न टांग दें। यूपी में जिस तरह शहरों के नाम बदले जा रहे हैं उसे देखते हुए आगरा का नाम घाघरा किए जाने का भी खतरा है।

खास खबर

ऑटो सेक्टर पर नए साल में भी मंदी का साया

नई दिल्ली। देश के ऑटो सेक्टर की बिक्री में गिरावट का सिलसिला नए साल में भी जारी है। जनवरी महीने में सभी श्रेणी के वाहनों की कुल बिक्री 13.83 प्रतिशत घटकर 17,39,975 इकाई रह गई. यही नहीं, यात्री वाहनों की बिक्री भी 6.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,62,714 इकाई रही। हालांकि इसके पहले 2019 का आखिरी महीना ऑटो सेक्टर के लिए कुछ बेहतर था और दिसंबर में मारुति, महिंद्रा और एमजी मोटर की कारों बिक्री में बहुत देखी गई थी। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी में तिपहिया को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के वाहनों की बिक्री घटी है. दोपहिया वाहनों की बिक्री करीब 16 फीसदी की गिरावट के साथ 13,41,005 इकाई रही। जनवरी में देश में कुल 75,289 कॉमर्शियल वाहन बिके जो जनवरी 2019 के मुकाबले 14.04 प्रतिशत कम हैं। इस दौरान तिपहिया वाहनों की बिक्री 12.69 प्रतिशत बढ़कर 60,903 इकाई पर पहुंच गई।सूत्रों के मुताबिक पिछले साल जनवरी में देश में 2 लाख 80 हजार 91 वाहन बिके थे।

10 मंत्रालयों पर 5 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में हुई लापरवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकार के मंत्रालयों से नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने विधि और न्याय मंत्रालय, महिला और कल्याण, समाजिक न्याय और अधिकारिता, ग्रामीण विकास सहित 10 केंद्रीय मंत्रालयों पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने बेघर और खानाबदोश लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराने और बिना आधार कार्ड वाले लोगों के लिए सामूहिक रसोई और खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने को कहा था।

डी.जी.पी. पर संशय, डी.आई.जी.- एस.पी. के थोकबंद तबादले

कमलनाथ सरकार ने सोमवार को अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है...।

डॉ शिशिर उपाध्याय

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 52 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसे अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी माना जा रहा है। नई सूची के मुताबिक 1988 बैच के अफसर प्रशासन के एडीजी कैलाश मकवाना को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नारकोटिक्स) बनाया गया है। वे पुलिस मुख्यालय में कामकाज देखेंगे। 16 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं. इनके अलावा सरकार ने आज पांच एडीजी, सहित कई आईजी, डीआईजी और सोलह जिलों में एसपी को डपर से उधर कर दिया है।

नई पुलिस जमावट

सवा साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही कमलनाथ सरकार ने अब पुलिसिया जमावट तेज कर दी है.राज्य सरकार ने एक साथ 52 पुलिस अफसरों के तबादले कर दिए हैं.मैदानी अफसरों से लेकर पीएचयू स्तर पर सरकार ने आला पुलिस अफसरों के कामकाज में बड़ा फेरबदल किया है.पुलिस विभाग के आज जारी तबादला आदेश में सरकार ने पांच एडीजी, सहित कई आईजी, डीआईजी और सोलह जिलों में एसपी को डपर से उधर कर दिया है।

सोलह जिलों में एसपी बदले

कमलनाथ सरकार का सबसे बड़ा पुलिस प्रशासनिक फेरबदल आज हो गया है. सरकार के सवा साल पूरे होने से पहले कमलनाथ सरकार ने एक साथ 52 पुलिस अफसरों को बदल दिया.सबसे महत्वपूर्ण पुलिस प्रशासन का जिम्मा कैलाश मकवाना से लेकर अजय कुमार शर्मा को जिम्मेदारी सौंप दिया गया है. वहीं सरकार ने लंबे समय से इंटेजिजेंस का जिम्मा संभाल रहे मकरंद देउरकर को हटाकर डी श्रीनिवास वर्मा को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है.

मामले में सीएम की नाराजगी के बाद उन्हें हटया गया है. तिवारी को पुलिस शेष पृष्ठ 7 पर

प्रमोशन में आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी घमासान

प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के 7 फरवरी के आदेश पर मचा सियासी घमासान, संसद में भी उठा मामला

कांग्रेस ने कहा था- भाजपा आरक्षण के खिलाफ है, सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका जाए

नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस और माकपा समेत विपक्षी दलों ने सोमवार को लोकसभा में हंगामा किया। सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद



गहलोत ने कहा- हम इसको लेकर उच्च स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि

अदालत में सरकार कभी इस मामले में पार्टी नहीं रही। गहलोत ने कहा- यह केस 2012 में

कांग्रेस ने रविवार को कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत है। एनडीए के सहयोगी दल लोजपा के सांसद चिराग पासवान ने भी लोकसभा में आरक्षण पर दिए फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। वह आरक्षण को संविधान से निकालना चाहती है। वे चाहते हैं कि एससी/एसटी कैटेगरी कभी आगे न बढ़े और यह जो कहा गया है कि आरक्षण मौलिक अधिकार ही नहीं है, ये भाजपा की साजिश है।

उत्तराखंड सरकार के पदोन्नति में आरक्षण नहीं देने पर सामने आया था। उस समय शेष पृष्ठ 7 पर

संघ के अधिकारी एवं कार्यालय आतंकी संगठनों के निशाने पर !

विस्फोटक लदी गाड़ी से कर सकते हैं हमला

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी और कार्यालय दुनिया के कई बड़े आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। हमले के लिए आतंकवादी आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) या विस्फोटकों से लदी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ताजा तथ्यों के मुताबिक महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्यों में इस तरह के हमले का ज्यादा खतरा है। आईबी द्वारा जारी तथ्यों में कहा गया, वैश्विक आतंकी समूहों से जुड़े अज्ञात लोग आने वाले दिनों में आरएसएस के



नेताओं, उनके दफ्तरों और पुलिस स्टेशनों पर हमले की योजना बना रहे हैं। आतंकवादी आईईडी या विस्फोटकों से लदी गाड़ी की मदद से आने वाले दिनों में ऐसे हमले को अंजाम दे सकते हैं। आईबी ने संबंधित राज्य सरकारों से खतरे को देखते हुए सुरक्षा कड़ी करने के लिए कहा है। एक उच्च अधिकारी ने दावा किया कि खुफिया अलर्ट के बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और असम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संघ के पदाधिकारियों की सुरक्षा की भी समीक्षा की जा रही है। दिसंबर में बेंगलुरु में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के समर्थन में रैली में शामिल होने गए संघ कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में जनवरी में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि मोहम्मद इरफान, शेष पृष्ठ 7 पर

फैसले पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

माकपा ने सरकारी नौकरियों और पदोन्नति में आरक्षण को अनिवार्य बताते हुए कहा है कि सरकार को इसे लागू करने में आ रही कानूनी बाधाओं को दूर करना चाहिए। इनके अलावा भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के दल लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने भी विरोधी सुर मुखर कर लिए हैं। उसका कहना है कि सरकार यदि आरक्षण में आ? आ रही कानूनी बाधा दूर नहीं करती तो संसद में मुद्दा उठाएंगे। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने कहा कि सरकार की पदों पर अजा/जजा की पदस्थापना सरकार का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि यह संविधान द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार है। पार्टी प्रवक्ता उदित राज ने कहा कि यह मामला बताता है कि भाजपा शासित राज्य और केंद्र सरकार में मतभेद हैं। वयोंकि ऐसे ही मामले में केंद्र ने

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए कोटा या आरक्षण की मांग करना मौलिक अधिकार नहीं है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने शुरुवार को कहा कि सरकारी सेवा में कुछ समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न दिए जाने का आंकड़ा सामने लाए बिना राज्य सरकारों को ऐसे प्रावधान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

प्लीज मोदी जी! बचा लीजिए... वरुण से भारतीयों ने भेजा संदेश

नई दिल्ली/तोक्यो। कर्रॉना वायरस के संक्रमण के बीच जापान के 'डायमंड प्रिसेज' लजरी वरुण पर फंसे भारतीयों ने विडियो संदेश भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। वरुण के वरु मेंबर टीम में शेफ की जिम्मेदारी संभाल रहे बिनय कुमार सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र



मोदी और संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए विडियो संदेश में कहा है कि वे बेहद डरे हुए हैं और जल्द से जल्द उन्हें यहां से निकालने का इंतजाम किया जाए। वरु मेंबर मोदी से मदद की गुहार लगाई है। वरुण के वरु मेंबर टीम में शेफ की जिम्मेदारी संभाल रहे बिनय कुमार सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र

महावीर मंदिर ट्रस्ट ने दिया राम मंदिर के गर्भगृह को सोने से बनाने का प्रस्ताव

लखनऊ। अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के मंदिर के गर्भ गृह को सोने का बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। श्रीराम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दिव्य मंदिर के निर्माण में गर्भगृह स्वर्ण पत्तलों से बनाने की बात कही गई है। ये प्रस्ताव पटना के महावीर स्थान न्यास समिति की तरफ से आया है। न्यास ने कहा है कि स्वर्ण गर्भ गृह में सोना लगाने का जितना भी खर्च आएगा,



वह न्यास वहन करेगा। महावीर न्यास समिति के सचिव पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल ने कहा है कि मंदिर को भव्य

राजनयिकों को कश्मीर का दौरा क्यों करा रही सरकार?

दरअसल, पिछले दौरे में यूरोपियन प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर दौरे पर जाने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वह 'गाइडेड टूर' के पक्ष में नहीं है और बाद में वह जाएंगे। इसके चलते पिछले दौरे में नें अमेरिकी राजदूत कैथेथ जस्टर समेत बांग्लादेश, वियतनाम, नॉर्वे, मालदीव, दक्षिण कोरिया, मोरक्को, नाइजीरिया और अन्य देशों के राजनयिक कश्मीर गए थे। ईयू के राजनयिकों ने कल था कि वे अपनी गर्मी से घुने गए नेताओं से मिलना चाहते थे।

कश्मीर में पीडीपी नेताओं से मिला था पिछला प्रतिनिधिमंडल

पिछले महीने दो दिवसीय कश्मीर दौरे पर विदेशी प्रतिनिधिमंडल को 15 कॉर्पस हेडक्वार्टर ले जाया गया। यहां राजनयिकों ने सेना के अधिकारियों ने कश्मीर के हालात के बारे में जानकारी दी। सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों के अलावा दल ने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अल्लाफ बुखारी से भी मुलाकात की थी। इस दौरान, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के 8 नेताओं ने भी राजनयिकों से मुलाकात की और राज्य के हालात के बारे में बताया।

टिप्पणी शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, किसी सार्वजनिक जगह को प्रदर्शन के लिए जाम नहीं जा सकता

शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट- ऐसे सड़क नहीं घेर सकते

शीर्ष अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

मामले की अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले की सुनवाई को 17 फरवरी तक के लिए टाल दिया है। शाहीन बाग में पिछले दो महीने से नागरिकता संशोधन ऐक्ट के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शन वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए

प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं

दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 50 दिनों से सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। इसके चलते वह मुख्य सड़क पर आवाजाही बंद है। इनके का दैनिक डाइवर्ट किए जाने से लोगों को हो रही परेशानी के खिलाफ वकील अनित साहनी और भाजपा नेता नंदकिशोर वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं, प्रदर्शन के दौरान 4 माह के बच्चे की मौत पर बहादुरी पुरस्कार प्राप्त छात्र गेन गुणरत्न सदावर्त ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी।

कोई अंतरिम आदेश तो नहीं दिया लेकिन इतना जरूर टिप्पणी की कि किसी

सार्वजनिक जगह को प्रदर्शन के लिए जाम नहीं किया जा सकता है। कोर्ट में



इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी। जस्टिस एस के कोल

प्रदर्शन में रास्ता बंद होने पर...

शीर्ष अदालत ने कहा- प्रदर्शन लंबे तक से जारी है, इसके लिए आम रास्ते को अनिश्चितकाल के लिए कैसे बंद कर सकते हैं। लोगों को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन निर्धारित स्थान पर ही किया जाना चाहिए। इस मामले में दूसरे पक्ष को सुनना भी जरूरी है। इसलिए तुरंत कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। कोर्ट ने इस मामले में भी केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि 58 दिन शेष पृष्ठ 7 पर

प्रदर्शन में बच्चे की मौत पर...

दो महिला वकीलों ने कोर्ट के स्वतंत्र संज्ञान लेने पर आपत्ति जताई। वकीलों ने कश्-प्रदर्शनस्थल पर जाने वाले बच्चों को स्कूलों में पाकिस्तानी और देशद्रोही कहा जाता है। इस पर चीफ जस्टिस एसए बोबे की बेच ने महिला वकील को फटकार लगाते हुए पूछा- क्या 4 माह का बच्चा ऐसे प्रदर्शनों में हिस्सा ले सकता है। वकीलों के मुद्दा भटकाने पर बेंच ने कहा- हम नहीं चाहते कि लोग अदालत का इस्तेमाल परेशानियां बढ़ाने के लिए करें।

करॉना: मोदी के ऑफर पर चीन, हमारी दोस्ती है

करॉना वायरस से पीड़ित चीन ने भारत द्वारा मदद की पेशकश की सराहना की

पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग को पत्र लिखकर की थी मदद की पेशकश

चीन में अबतक 900 लोगों की जान ले चुका है करॉना वायरस

चीन का हुबेई प्रांत करॉना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है

पेइचिंग। पीएम मोदी ने करॉना वायरस का प्रकोप खेल रहे चीन को मदद की पेशकश की थी जिसकी चीन ने सराहना की है। पीएम मोदी की इस पेशकश की सराहना करते हुए चीन ने कहा कि यह भारत की पेइचिंग के साथ दोस्ती को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। पीएम मोदी के पत्र पर चीन की यह प्रतिक्रिया काफी मायने रखती है, खासकर तब जब गाहे बगाहे भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव भी देखने को मिलता है। आपको बता दें कि



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को पत्र लिखकर करॉना वायरस से

मोदी ने करॉना वायरस को लेकर चिनफिंग और चीन के लोगों के प्रति एकजुटता का इजहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने खत में चीन के हुबेई प्रांत में फंसे 650 भारतीयों को एयरलिफ्ट करने में मदद के लिए चिनफिंग की तारीफ भी की है।

चीन में 900 लोगों की जान ले चुका है करॉना वायरस

गौरतलब है कि हमारा पड़ोसी देश चीन इस वक्त करॉना वायरस

चीन ने भारत के प्रति जताया आभार
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, हम करॉना वायरस के खिलाफ चीन की लड़ाई में भारत के समर्थन के प्रति आभार जताते हैं और सराहना करते हैं। प्रवक्ता ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में मोदी की ओर से चिनफिंग को लिखे गए पत्र के बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, भारत की सद्भावना का यह कदम चीन के साथ उसकी दोस्ती को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है।

के प्रकोप से बुरी तरह पीड़ित है। इस वायरस की वजह से अबतक चीन में तकरीबन 900 लोगों की जान जा चुकी है। करॉना वायरस

से चीन का हुबेई प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस प्रांत की राजधानी वुहान में बहुत बुरी स्थिति है। लोगों को ऐहतियातन उनके घरों में ही

एक तरह से कैद करना पड़ा है ताकि वायरस से प्रसार को रोक़ा जा सके।

दर्दनाक : बेरोजगारी से परेशान पिता ने की दो बच्चों की गला घोटकर हत्या, फिर मेट्रो के आगे कूदकर की खुदकुशी

नई दिल्ली(ए.)। राजधानी के शालीमार बाग इलाके में रविवार (9 फरवरी) रात दो बच्चों की गला घोटकर हत्या करने के बाद एक शख्स द्वारा मेट्रो के आगे कूदकर खुदकुशी करने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। प्रारंभिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि हत्यारोपी पिता की कुछ दिनों से बेरोजगार था। इस कारण उसकी आर्थिक हालात ठीक नहीं थी। इस बात को लेकर वह परेशान था और डिप्रेशन में चल रहा था। इस आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया है। बहरहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच आरंभ कर दी है। आरोपी की पत्नी से पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है।

आरएसएस नेता भैय्याजी जोशी बोले, हिंदू मतलब बीजेपी नहीं

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेता सुरेश 'भैय्याजी' जोशी ने कहा कि आपका सवाल कहना है कि हिंदू ही हिंदू समुदाय का दुश्मन बन रहे हैं, यानी बीजेपी। हिंदू समुदाय का मतलब बीजेपी नहीं है। उनकी यह टिप्पणी संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का विरोध करना हिंदुओं का विरोध करने के बराबर नहीं है। जोशी ने यह बात यहां पास स्थित दोना पाउला में विश्वगुरु भारत पर भाषण के तहत प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान कही। इस सवाल पर कि 'क्यों हिंदू अपने ही समुदाय के दुश्मन बन रहे हैं', उन्होंने कहा कि हमें भाजपा के विरोध को हिंदुओं का विरोध नहीं मानना चाहिए। यह एक राजनीतिक लड़ाई है जो चलती रहेगी। इसे हिंदुओं से नहीं जोड़ना चाहिए। जोशी ने कहा, 'एक हिंदू अपने साथी (हिंदू) के खिलाफ लड़ता है क्योंकि वे धर्म भूल जाते हैं। यहां तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज को भी अपने ही परिवार से विरोध का सामना करना पड़ा था। जहां भ्रम और आत्मकेंद्रित व्यवहार होता है, विरोध होता है।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफदिल्ली से लेकर कर्नाटक तक लोगों ने किया मार्च



नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship amendment act) के खिलाफदेश के कई हिस्सों में प्रदर्शन अब भी जारी है। इस बीच सोमवार को लोग नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर पर दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर संसद तक मार्च कर रहे हैं। उधर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरु में बिलात मस्जिद के नजदीक महिलाओं ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), एनआरसी और एनपीआर पर प्रदर्शन किया। उधर, दिल्ली के शाहीन बाग में दो महीने से भी ज्यादा से लोग एक जगह पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें अधिकतर महिला और बच्चे शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों को हटाने वाली मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि विरोध से दूसरों को परेशानी न हो, ऐसा अनिश्चित काल के लिए नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इतने समय तक आप रोड कैसे ब्लॉक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी की होगा।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ संसद मार्च, पुलिस से भिड़े, लहराई चूड़ियां

जामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 से निकले मार्च को ओखला के होली फैमिली हॉस्पिटल के नजदीक रोका गया

इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, कुछ प्रदर्शनकारी घायल

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राजधानी में विरोध-प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो गया है। रविवार को संसद तक मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। इस दौरान



कुछ प्रदर्शनकारी जखमी भी हुए हैं। संसद तक प्रोटेस्ट मार्च को रोकने जाने से नाराज कुछ महिला प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस की

तरफ चूड़ियां भी लहराईं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए क्योंकि वह मार्च को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। दिल्ली

संसद तक मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों को ओखला में रोका गया

जामिया से संसद तक मार्च के एलान के बाद से ही दिल्ली पुलिस ने जामिया और आस-पास के क्षेत्रों को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया था। जामिया के छात्रों और पूर्व छात्रों के संगठन जामिया को-ऑर्डिनेशन कमिटी (छूष्ट) ने सीएए के विरोध में संसद तक मार्च का एलान किया था। प्रशासन ने इस मार्च को अनुमति नहीं दी है। सैकड़ों प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन ओखला में होली फैमिली हॉस्पिटल के नजदीक पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक लिया।

कागज नहीं दिखाएंगे...हल्ला बोल के नारे

प्रदर्शनकारियों ने जामिया के गेट नंबर-7 से अपना मार्च शुरू किया। प्रदर्शनकारी कागज नहीं दिखाएंगे और जब नहीं डरे हम गोरों से तो क्यों डरे हम औरों से जैसे नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन में कई महिलाएं भी थीं। हाथों में कई लोग तिरंगा थामे हुए थे और हल्ला बोल के नारे लगा रहे थे।

महाराष्ट्र की 24 वर्षीय टीचर ने तोड़ा दम, मनचले ने पेट्रोल छिड़ककर लगाई थी आग

मुंबई(ए.)। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पिछले हफ्ते जिस 24 वर्षीय महिला टीचर को जिंदा जलाया गया था उसने जिंदगी के लिए लंबे संघर्ष के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। नागपुर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इस बात की जानकारी दी, जहां पर उस टीचर को बुरी तरह जलने के बाद इलाज किया जा रहा था।



टीचर के गांव का ही रहनेवाले है आरोप

वर्धा की पुलिस अधीक्षक बसराज तेजी ने आईएनएस से कहा, हमने घटना के तुरंत बाद 27 वर्षीय आरोपी विक्की नागरे को पकड़ लिया। उन्होंने आगे कहा, वह और पीड़िता एक ही गांव दारोदा के रहने वाली हैं। 25 वर्षीय पीड़िता पास के ही मातोश्री आशादाई कुंवर कॉलेज में पार्टटाइन लेक्चरर के रूप में पढ़ाती थीं।

डीएसडब्ल्यू ने प्रिंसिपल को किया तलब

नई दिल्ली(ए.)। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में छह फरवरी को एनुअल फेस्ट के दौरान छात्रों के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में बवाल बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। इस घटना के विरोध में गार्गी कॉलेज के गेट के बाहर 100 से अधिक छात्राओं ने इस संबंध में प्रदर्शन किया। संसद में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि छेड़छाड़ के मामले में बाहरी तत्व शामिल रहे



और संस्थान प्रशासन से कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेने के बाद सोमवार को कॉलेज जाकर छात्राओं से पूछताछ की।

क्या हुआ था गार्गी कॉलेज में

सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, छह फरवरी को कॉलेज फेस्ट 'रेवरी' के दौरान शान करीब साढ़े छह बजे नशे में धुत पुरुषों के समूह ने कॉलेज के प्रवेश द्वार पर धावा बोल दिया और अंदर घुस गए। छात्राओं ने आरोप लगाया कि 'पैपिड एवशन फेस' और दिल्ली पुलिस के जवान वहीं गेट के पास तैनात थे, जहां से ये पुरुष कथित तौर पर अंदर आए। नाम उजागर न करने की धरत पर एक छात्रा ने कहा, 'वह सुरक्षा में भारी चूक थी। छात्राओं को गलत तरीके से छुआ गया, छेड़छाड़ की और उन पुरुषों द्वारा हाथापाई भी की गई, निनकी उम्र 35 साल के आसपास लग रही थी। कॉलेज ने सुरक्षा का दावा किया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी कॉलेज परिसर में ऐसी कोई घटना हो सकती है।'

समन के मुताबिक, कॉलेज प्रिंसिपल प्रेमिला कुमार को 13 फरवरी को दोपहर दो बजे पेश होकर जवाब देना है। वहीं डीसीपी

साउथ ने बताया है कि फ्राइम अगेंस्ट वूमैन सेल की जांच अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है।

पुलवामा हमला: दिग्विजय सिंह ट्वीट कर बोले-मोदी-शाह का काम हो गया

नई दिल्ली(ए.)। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले के शहीदों का मामला उठाते हुए सोमवार को कहा कि शहीदों के परिजनों को एक साल बीतने के बावजूद मदद नहीं मिली है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि पुलवामा हमले का एक साल हो गया है। शहीद की पत्नी मदद के लिए गुहार लगा रही है। अब तो सरकार को सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि 'मोदी-शाह' का काम हो गया है और उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव (लोकसभा चुनाव) जीत लिया।

पश्चिम बंगाल में भी फ्री बिजली का ऐलान
3 महीने में 75 यूनिट खपत करने वालों को नहीं देना होगा बिल

कोलकाता(ए.)। दिल्ली सरकार की तर्ज पर पश्चिम

रुपए के बजट की घोषणा की है। राज्य के वित्त

मंत्री ने अपने भाषण में कहा पश्चिम बंगाल के

बंगाल की सरकार ने भी मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। अपने फैसले में ममता सरकार ने कहा है कि तीन महीने में 75 यूनिट बिजली की खपत करने वालों से बिल नहीं लिया जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दे रही है। इस विधानसभा चुनाव में फ्री बिजली को लेकर खूब चर्चा हुई। ममता सरकार ने आज अपना बजट विधानसभा में पेश किया है। 2,55,677 करोड़



लिए इस मद में 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। झारखंड सरकार भी दिल्ली की तरह झारखंड में घरेलू उपयोग के लिए फ्री बिजली देने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा विभाग 100 यूनिट फ्री बिजली का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की घोषणा में शामिल है।

दिल्ली ताज सभी एग्जिट पोल में भाजपा की हार की भविष्यवाणी

बीजेपी कर रही है दिल्ली में सरकार बनाने का दावा?

नई दिल्ली (वार्ता)। सारे एग्जिट पोल में भले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार की वापसी की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन बीजपी आत्मविश्वास से भरी हुई है कि 11 फरवरी को जब ईवीएम खुलेंगे तो सारे आकलन धरे रह जाएंगे और दिल्ली में उसकी जीत होगी। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के 70 में से 45 सीटें जीतने का दावा कर चुके हैं तो पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी राजनीतिक पंडितों को चुनौती देने के अंदाज में ऐलान कर चुके हैं कि पार्टी 48 सीटें



हासिल कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के इस आकलन का आधार क्या है? और वह सभी एग्जिट पोल के गलत होने का

दम क्यों भर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उसके दावे के तीन आधार हैं। अंतिम दो घंटों में 17% के करीब वोटिंग, पार्टी का आतिरक सर्वे और चुनाव

खत्म होने के बाद 'आप' का चुनाव आयोग पर हमालवर होना। एक बीजेपी नेता ने बताया कि पार्टी ने जो सर्वे कराया है, उसके मुताबिक बीजेपी दिल्ली में कम-से-कम 38 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इस सर्वे के अनुसार आप को 30 से 32 सीटें मिल सकती है।

पार्टी नेताओं का आकलन है कि अंतिम दो घंटों में हई 17% वोटिंग को किसी एग्जिट पोल में शामिल नहीं किया गया है। पार्टी नेताओं के तर्क हैं कि जब 6 बजे एग्जिट पोल्स में आंकड़े दिखा दिए गए तो इसका साफमतलब है

कि इसमें दोपहर तक के ही संपल शामिल किए गए होंगे, जबकि दिल्ली में अंतिम घंटों में बंपर वोटिंग हुई है।

पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने दो टूटवीट्स करके इस ओर इशारा किया है। उन्होंने लिखा है, 'तीन फैक्टर्स पर गौर करने की जरूरत है। आखिर के दो घंटे में करीब 17% मतदान, ईवीएम को लेकर आम आदमी पार्टी का नैसिंह और तीसरा फैक्टर है, एग्जिट पोल के नतीजे।' उन्होंने सवाल पूछा है कि एग्जिट पोल के अलावा कुछ और होने की संभावना दिख रही है?

उन्होंने अगले ट्वीट में 62.59% वोटिंग का हवाला देते हुए कहा कि पिछले चुनाव से केवल 5% कम और लोकसभा चुनाव से 2% अधिक वोटिंग हुई है, इससे चुनाव एग्जिट पोल्स के आकलनों के विपरीत एकदम खुला हुआ है।

चुनाव खत्म होने और एग्जिट पोल्स में जीत के भविष्यवाणी के बाद भी आम आदमी पार्टी जिस तरह से ईवीएम और चुनाव आयोग पर हमलावर है, उससे भी बीजेपी की उम्मीदें बढ़ी हैं।

यूपी के मंत्री रघुराज सिंह की बुर्के पर रोक की मांग, कहा- आतंकी पहचान छुपाने के लिए करते हैं इस्तेमाल

नई दिल्ली(ए.)। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए एक और विवाद खड़ा कर दिया है।



मंत्री ने कहा बुर्के का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा अपनी पहचान छिपाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने यह जाहिर तौर पर आगरा में शाहजमाल इलाके में महिलाओं द्वारा सीएए के खिलाफफिए जा रहे विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में कहा। मंत्री ने आगे कहा कि बुर्का पहनना अरब देशों में शुरू हुआ और यह भारतीय रिवाज नहीं है।

उन्होंने कहा कि भारत को इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल श्रीलंका में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के बाद श्रीलंका ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों घायल हुए थे।

संपादकीय

कागज पर कोहराम कब तक

नए नागरिकता कानून का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे तो नए नागरिकता कानून को लेकर देश भर में छिटपुट विरोध प्रदर्शन हुए है लेकिन देश की राजधानी नई दिल्ली के शाहीन बाग में लगातार कुछ लोग सड़क को रोक कर धरना प्रदर्शन कर रहे है। डेढ़ माह से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन शाहीन बाग को राजनीति का अखाड़ा बनाने वाले लोग अभी भी वहां डटे हुए है। उनका कहना है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। शाहीन बाग में चल रहे तथाकथित आंदोलन के 8 फरवरी को नई दिल्ली विधानसभा चुनाव निपटने के बाद खत्म होने की उम्मीद थी लेकिन अभी भी शाहीन बाग में कागज न दिखाने वालों की भीड़ जुटी हुई है। इस बीच अससुद्दीन ओवैसी ने फिर भड़काउ भाषण दिया है कि वे भी कागज नहीं दिखाएंगे। अगर उसे कागज मांगा गया तो वे अपना सीना दिखाएंगे और कहेंगे कि लो गोली मार दो। जाहिर है कुछ नेता नए नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर देश में दंगा फसाद कराने की कोशिश कर रहे है। सरकार ने कई बार स्पष्ट कर दिया है कि नए नागरिकता कानून ने किसी को देश से निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद नए नागरिकता कानून को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित की जा रही है और लोगों को सरकार के खिलाफ बरगलाया जा रहा है। नतीजतन शाहीन बाग का प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आंदोलन के नाम पर किसी सार्वजनिक सड़क पर कब्जा करना असंवैधानिक है। लेकिन शाहीन बाग वालों को सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं है। अब चूँकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव निपट चुके है और आज चुनाव परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। इसके बाद शाहीन बाग को तत्काल प्रभाव से खाली कराना चाहिए। ताकि लाखों लोगों को इस आंदोलन के चलते जो असुविधा हो रहा है उससे उन्हें मुक्ति मिले। दिल्ली में जिसकी भी सरकार बने उसकी पहली प्राथमिकता शाहीन बाग को खाली कराना होना चाहिए।

विचार

जातीय आरक्षण के विरुद्ध फैसला

सर्वोच्च न्यायालय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले पर देश के अखबारों और चैनलों का बहुत कम ध्यान गया है। फैसले का मैं इसलिए स्वागत करता हूँ कि यह देश से जातिवाद को खत्म करने में बहुत मदद करेगा। फैसला यह है कि आप किसी भी सरकार को जाति के आधार पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हमारे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों को आरक्षण देने की प्रथा चली आ रही है। सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या इनके अनुपात में काफ़ी कम है। उनके साथ सदियों से अन्याय होता रहा है। ये सब लोग मेहनतकश होते हैं। हाड़तोड़ काम करते हैं। हमारे राजनीतिक दलों ने इस अन्याय को ठीक करने के लिए एक बहुत ही सस्ता-सा रास्ता निकाल लिया है। वह है, सरकारी नौकरियों में उनके आरक्षण दे दिया जाए। कोई आदमी किसी पद के योग्य है या नहीं है, यदि वह अनुसूचित है या पिछड़ा है तो उसे उस पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। इन जातियों के लोगों ने इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया था। लेकिन कुछ वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ों में जो क्रीमी लेयर याने मलाईदार परत याने संपन्न लोग हैं, उनके आरक्षण को अनुचित बताया और अब उसने यह एतिहासिक फैसला दिया है कि अनुसूचितों को आरक्षण देना राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करेगा। यह अनिवार्य नहीं होगा। यह अनुसूचितों का मूलभूत अधिकार नहीं है। उसने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 2008 में दिए गए फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि उत्तराखंड सरकार को पूरा हक है कि वह समस्त सरकारी पदों को बिना किसी आरक्षण के भर सके। संविधान की धारा 16 में आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है, वह राज्य सरकारों को इस बात की छूट देता है कि वे अपनी जांच के आधार पर तय करें कि उन्हें कोई पद आरक्षित करने हैं या नहीं ? यही सिद्धांत पदेन्रतियों पर भी लागू होता है। मुझे विश्वास है कि सभी राज्य और केंद्र सरकारें इस फैसले पर सख्ती से अमल करेंगी। तब प्रश्न यह होगा कि हमारे करोड़ों पिछड़े, ग्रामीण, गरीब भाइयों को न्याय कैसे मिलेगा ? उनके साथ न्याय करना बेहद जरूरी है। राष्ट्र का यह नैतिक कर्तव्य है। दो तरीके हैं। पहला, उन सबके बच्चों के लिए शिक्षा, भोजन और वस्त्र मुफ्त दिए जाने चाहिए और दूसरा, मानसिक और शारीरिक श्रम की कीमतों में एक से दस गुने से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। वे अपनी योग्यता से आगे बढ़ेंगे। किसी की दया के मोहताज नहीं होंगे। स्वाभिमानी राष्ट्र का निर्माण होगा।

टेक - ज्ञान

मार्च में लॉन्च होगा सस्ता आईफोन

नई दिल्ली। प्रीमियम स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ऐपल के आईफोन SE2 के बारे में कई लीकस अभी तक सामने आ चुके हैं। यह कंपनी का अपरेंडैबल आईफोन होगा। अभी तक सामने आ चुके रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि इस आईफोन को आईफोन 9 भी नाम दिया जा सकता है।

पाठकों की बात

भद्दी कहानी और नही

अगर ‘शिकारा’ केवल एक प्रेम कहानी है, तो इससे भद्दी कहानी और नही हो सकती कुछ भी। तब अपने जमीर के साथ-साथ कश्मीरी हिन्दुओं की पीड़ा को भी बेच देने के लिए विधु विनोद की मलानत होनी चाहिये। मुजम्मत और मरम्मत भी। - **पंकज कुमार झा**

स्त्री का प्रेम

स्त्री का प्रेम ... पूरे पृष्ठ पे रहता है और जिंदगी के तमाम कार्य हाशिये पर और पुरुष का प्रेम हाशिये पर रहता है तथा तमाम कार्य पृष्ठ पर ... उसके लिए किसी के व्यक्तिगत प्रेम से बढ़कर ...सामाजिक-विजय की कामना होती है???...उसे किसी का प्रेम भी इसलिए चाहिए ताकि सामाजिक-विजय के लिए ऊर्जा मिलती रहे??

- **तनु युग भारद्वाज**

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

ख़ास प्ताती | शायद कांग्रेस के खेल ने भी

शायद कांग्रेस के ‘ खेल ’ ने भी आप पार्टी को अच्छ फायदा पहुंचाया और यह खेल प्रियंका वाड़ा के दिमाग की उपज थी । कांग्रेस अब एक नई तरह की नकारात्मक राजनीति करने लगी है इसका लाभ भी उसे कुछ राज्यों में मिला है और भाजपा को नुकसान । संभवतः भाजपा दिल्ली में कांग्रेस की इस खामोशी के खेल को समय रहते समझ नहीं पाई । बहरहाल देखते हैं क्या आता है वास्तविक चुनाव परिणाम ।

- **एल.एस. बिष्ट**

जहर की खेती देखी है कभी...

जहर की खेती देखी है कभी आजकल कितनी बोई जा रही है हर तरफ. सोच जहरीली बाते जहरीली आदमियत तक जहरीली हो चुकी है यहां तक क कि मासूम बच्चो के मुंह से भी अब जहर टपकने लगा है कहा: लेके जा रहे ??और क्या पाना चाह रहे?? ऐसा ना हो कि ये जहर एक दिन सब कुछ खत्म कर दे. जिसे देख ये सता के लोलुप भेड़िए ..उच्चो अटालिका पर बैठ सिर्फ जहरीला अट्टहास करते रहे। - **मोनिका अस्थाना**

जब भी चुनाव होता है मतदाता मतदान करते हैं

जब भी चुनाव होता है मतदाता मतदान करते हैं जीतने वाला जीतता है हारने वाले हारते हैं पर चुनाव परिणाम आते तक डरा सहमा बेचारा ई.वी.एम. होता है क्यों ??? वी.वी.पेट.साथ होता है, फिर भी सवालों से घिरा होता है क्यों ??? चुनाव परिणाम पक्ष में तो ई.वी.एम. अच्छ न आए तो ई.वी.एम. ख़राब बेचारा!!!! ई.वी.एम.!!!

- **वर्षा ठाकुर**



डॉ शिशिर उपाध्याय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने साल की पहली मौद्रिक नीति में मुख्य ब्याज दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। तमाम बैंक इसी दर पर आरबीआई से कर्ज उठाते हैं और यह 5.15 फीसदी पर ही स्थिर रहेगी। ऐसे में कर्ज लेने वालों को भारत के केंद्रीय बैंक की तरफ से कोई राहत नहीं मिलने जा रही है, हालांकि इसे भी आरबीआई का नरम रुख माना जा रहा है।

आरबीआई की राहत का इंतजार ?

रिजर्व बैंक का कहना है कि वृद्धि दर की तुलना में मुद्रास्फीति की तेज रफ्तार को देखते हुए उसने रेपो रेट में कटौती न करने का फैसला किया। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच दूध और दालों की कीमत में बढ़ोतरी के कारण जनवरी-मार्च तिमाही के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया गया है। आरबीआई ने इसे बहुत अनिश्चित बताते हुए कहा कि भविष्य में खुदरा महंगाई का अनुमान खाद्य महंगाई, कच्चे तेल की कीमत और सेवाओं के लिए इनपुट लागत के आधार पर लगाया जाएगा। वैसे उसने माना कि रबी फसलों के बाजार में आने से खाद्य महंगाई की दर दिसंबर में दर्ज उच्च स्तर से नीचे आएगी।

आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में वृद्धि दर 6.2 फीसदी रह सकती है। मौद्रिक नीति में कमर्शल रीपल्टी लोन लेने वालों के लिए बड़ा निर्णय किया गया है। उचित कारणों से हुई देरी पर अब लोन डाउनग्रेड नहीं होगा। यानी अगर कोई डिवेलपर किसी वजह से कर्ज समय पर नहीं चुका पाता है तो उसके कर्ज को एक साल तक पनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। रीयल्टी सेक्टर को इससे काफी राहत मिली है और कारोबारी जगत ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई है। पॉलिसी के ऐलान के बाद शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों निफ्टी और सेंसेक्स में उछाल देखने को मिला। रिजर्व बैंक का रुख चूँकि नरमी का है, इसलिए आगे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बनी हुई है।

बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को देखते हुए विश्लेषकों को लग रहा था कि 2019 में रेपो रेट में रिकॉर्ड पांच बार कटौती करने के बाद रिजर्व बैंक नए साल की शुरुआत ब्याज में सख्ती के साथ कर सकता है। अनुमान था कि 2020-21 में उसे बड़े राजकोषीय घाटे

का दबाव झेलना पड़ेगा इसलिए रेपो रेट बढ़ाना उसके लिए अधिक स्वाभाविक है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बढ़ाकर जीडीपी का 3.8 फीसदी कर दिया है। पहले इसे 3.3 प्रतिशत रखा गया था। आरबीआई ने अनुमान जाहिर



किया कि कारोबारी साल 2020-21 में मॉनसून सामान्य रहेगा, जिससे अगले कारोबारी साल की पहली छमाही में खुदरा महंगाई दर घटकर 5.0-5.4 फीसदी पर और अगले कारोबारी साल की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2020) में और घटकर 3.2 फीसदी पर आ सकती है। बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी ग्रोथ छह फीसदी रहेगी, जबकि उसके पहले छह महीने में वृद्धि दर 5.5 फीसदी से छह फीसदी रहने का अनुमान है।

नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करके इस बात का संकेत दिया है कि वह महंगाई

पर नजर रखे हुए है और आने वाले दिनों में भी खुदरा महंगाई बढ़ने को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसे देखते हुए नीतिगत दरों में और कटौती संभव नहीं है। उम्मीद तो यह की जा रही थी कि मंदी के माहौल से निपटने के लिए रिजर्व बैंक एक

फैसला महंगाई को काबू करने के लिहाज से बड़ा कदम है।रिजर्व बैंक के समक्ष चुनौतियां काफी हैं। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए उद्योग जगत को तैयार करना है। केंद्रीय ने ब्याज दरें घटाने के लिए और छोटे उद्योगों सहित आम उपभोक्ताओं को मकान और

वाहन खरीदने के लिए कर्ज देने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनसे बाजार में जान आने की उम्मीद है। सस्ता कर्ज देने में बैंक झिझकें नहीं, इसके लिए केंद्रीय बैंक ने व्यावसायिक बैंकों के लिए नगद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) संबंधी नियम में ढील दी है। इसके अलावा बैंकों को एक लाख करोड़ की रकम बहुत ही कम दर पर एक से तीन साल तक के लिए देने का फैसला किया है। अगर ये कवायद सफल रहती है तो उम्मीद है उद्योगों का पहिया चल निकलेगा और मांग भी निकलेगी। पर अभी कुछ महीने तो महंगाई पीछ नहीं छोड़ने वाली।

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति रेपो और रिवर्स रेपो दरें करती है। पर इस बार रेपो दर को पिछले स्तर यानी 5.15 फीसद पर ही स्थिर रखने का फैसला किया गया। केंद्रीय बैंक ने आने वाले दिनों में महंगाई के जो अनुमान व्यक्त किए हैं, उससे लग रहा है कि महंगाई की मार से जल्द ही पिंड नहीं छूटने वाला। हालांकि दिसंबर-जनवरी के मुकाबले थोड़ी नरमी की उम्मीद जरूर है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्याज के दाम और नीचे आएंगे, इसलिए चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में महंगाई में सोच सकता है। साथ ही, रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि ब्याज दरों में कटौती के लिए अब नीतिगत दरों पर निर्भर नहीं रहा जाएगा, बल्कि कर्ज सस्ता करने और कर्ज का प्रवाह बढ़ाने के लिए दूसरे उपाय किए जाएंगे। रिजर्व बैंक का यह

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

क्या वर्तमान डीजीपी हट ही जाएंगे ?

डीजी साइबर और हनी ट्रैप मामले की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख राजेन्द्र कुमार नए डीजी बनेंगे, इसमें संदेह नहीं रहा। सरकार ने इस पद के लिए यूपीएससी द्वारा भेजे पैनल को अस्वीकार कर दिया है। सोमवार को इस बारे में हाईकोर्ट में राज्य सरकार को उत्तर देना है। आशा है कि इसी दिन सरकार नया एसआईटी प्रमुख बनाए जाने की अनुमति हाईकोर्ट से मागेगी। इसके बाद किसी भी दिन नए डीजीपी के नाम की घोषणा हो सकती है। सिंह की पदस्थापना कहा होगी, यह अभी निश्चित नहीं है। वे एक साल की कांरिस सरकार में हटाए जाने वाले दूसरे डीजीपी हो सकते हैं। इससे पहले ऋषि कुमार शुक्ला को हटया गया था। बाद में शुक्ला सीबीआई डायरेक्टर बने। सरकार और सिंह के बीच चार महीने से खींचतान चल रही है और मुख्यमंत्री डीजीपी की कार्यशैली से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। हाल ही में राजगढ़ की कलेक्टर को लेकर पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद यह अनबन और बढ़ गई है। वीके सिंह से मुख्यमंत्री कमलनाथ इतने नाराज हैं कि उन्होंने पिछले लगभग 25 दिनों से उन्हें मिलने का समय ही नहीं दिया गया। यह नाराज किस बात को लेकर है ? पता नहीं।सीएम डीजीपी से क्या चाहते हैं? यह बात अभी तक नहीं है। आश्चर्य है कि पुलिस के मुखिया से मिलने के लिए सीएम के पास वक्त ही नहीं है ?

इधर सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह डीजीपी



वीके सिंह के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा है कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मतलब साफ है कि सरकार के मंत्रियों और सीएम के बीच बिल्कुल सामंजस्य नहीं है। कौन

किसको हट रहा है। कौन किसको रख रहा है, भ्रम की स्थिति है। वैसे भी डीजीपी का कार्यकाल अच्छा माना गया है। लगता है सरकार को ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी ही पसंद नहीं हैं। वैसे वीके सिंह को हटाए जाने के पीछे ये तीन बड़ी

लघु कथा- सच्ची मेकर

इस दीपावली वह पहली बार अकेली खाना बना रही थी। सच्ची बिगड़ जाने के डर से मध्यम आँच पर कड़ाही में रखे तेल की गर्माहट के साथ उसके हृदय की गति भी बढ रही थी। उसी समय गिरसट-गाइंडर जैसी आवाज निकालते हुए मिनी स्कूटर पर सवार उसके छोटे भाई ने रसोई में आकर उसकी तंद्रा मंग की। वह उसे देखकर नाक-मुंह सिकोड़कर घिझाया, गमा दीदी बढा रली हैड नैं नही खाऊंगा आज खाना! सुनते ही वह खीज गयी और तीखे स्वर में बोली, चुप कर पोल्थूशन मेकर, थाम को पूरे घर में पटाखों का धुँआ करेगा। उसकी बात पूरी सुनने से पहले ही भाई स्कूटर दौड़ाता रसोई से बाहर घला गया और बाहर बैठी मौँ का स्वर अंदर आया, दीदी को परेशान मत कर, पापा आने वाले हैं, आते ही उन्हें खाना खिलाना है। लेकिन तब तक वही हो गया था जिसका उस डर था, ध्यान बंटने

से सच्ची थोड़ी जल गयी थी। घबराहट के मारे उसके हाथ में पकड़ा हुई मिर्ची का डिब्बा भी सच्ची में गिर गया। वह और घबरा गयी, उसकी आँखों से आँसू बहते हुए एक के ऊपर एक अतिरुमण करने लगे और वह सिर पर हाथ रखकर बैठ गयी। उसी मुद्रा में कुछ देर बैठ रहते के बाद उसने देखा कि छिड़की के बाहर खड़ा उसका भाई उसे देखकर मुँह बना रहा था। वह उठी और छिड़की बंद कराने लगी, लेकिन उसके भाई ने एक पैकेट उसके सामने कर दिया। उसने चौक कर पूछा, क्या है? भाई धीरे से बोला, पनीर की सच्ची है, सामने के होटल से लाया है। उसने हैरानी से पूछा, वरूँ लाया? रूपये कहीं से आये? भाई ने उत्तर दिया, क्रैकर्स के रुपयों सेज थोड़ा पोल्थूशन कम करुंगा और वरूँ लाया! अंतिम तीन शब्दों पर जोर देते हुए वह हँसने लगा।

आज का इतिहास

नई दिल्ली ।1613 - मुगल बादशाह जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूत में कारखाना लगाने की अनुमति दी। 1720 - स्वीडन तथा प्रशिया के बीच शांति समझौता। 1793 - प्रशिया की सेना ने नीदरलैंड के वेनलो पर कब्जा किया। 1814 - यूरोपीय देश नॉर्वे ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1889 - जापान में मेजी संविधान को अंगीकार किया गया। 1919 - प्रेडरिक एबर्ट जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गये। 1953 - सोवियत संघ ने इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़े। 1964 - ताइवान ने फ्रांस के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़े। 1968 - जनसंघ के संस्थापक पंडित दीन दयाल उपाध्याय की मुगलसराय में हत्या। 1979 - ईरान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खमेनेई का सत्ता पर कब्जा।



- **कवि सुशील भोले**

को भी यह लगता है कि सरकार की नीतियाँ एवं बाजार भाव में फर्क आ गया है, लिहाजा जिसे केंद्र सरकार ने भी आयकर की धारा में अंतर के प्रतिशत को बढ़ाकर स्वीकार किया है। उन्होंने आगे बताया कि इतिहास में पहली बार आयकर में 2 रेजीम लायी गयी हैं। इसको आसान शब्दों में ऐसा समझा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम द्वारा सभी प्रचलित ह्यूट को त्याग दे तो उसे सीधे-सीधे कार की गड़ना करनी एवं पटना है।

जिन चौक-चौहासों पर यातायात पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनमें शारदा चौक, जय स्तम्भ चौक, घड़ी चौक, भगत सिंह चौक, तेलीबांदा चौक, रेलवे स्टेशन चौक, टर्निंग पाइंट चौक, पंडरी बस स्टैंड चौक समेत 10 चौक पर चोकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

सीए राजेश मेहता ने बताया कि जमीन या अचल संपत्ति की बिक्री पर अगर बाजार भाव एवं लेन-देन की राशि के अंतर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया है तो इस फैसले को इस तरह से समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार

को भी यह लगता है कि सरकार की नीतियाँ एवं बाजार भाव में फर्क आ गया है, लिहाजा जिसे केंद्र सरकार ने भी आयकर की धारा में अंतर के प्रतिशत को बढ़ाकर स्वीकार किया है। उन्होंने आगे बताया कि इतिहास में पहली बार आयकर में 2 रेजीम लायी गयी हैं। इसको आसान शब्दों में ऐसा समझा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम द्वारा सभी प्रचलित ह्यूट को त्याग दे तो उसे सीधे-सीधे कार की गड़ना करनी एवं पटना है।

जाह्नवी कपूर ने कहा, जब मेरी फिल्म 'धडक' रिलीज

वैलटाइस वीक में
फ़िल्मों तो आपने देखा
वाला प्यार। देखें, बोलें
है कितना प्यार। सल
और जान्हवी की
से लोग
करने के
इनहाउट
फ़िल्मों
में भी
लेक
डेडी
ही
अ
दे

के बाद
राम
न
ल
थमाई
तीक्ष्ण
होगी इसके बारे

अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं
आई है। सामने आई रणवीर सिंह की
फोटो में एक्टर वाइड और ऑरेंज शर्ट
में दिख रहे हैं। उन्होंने छोटी मुछे
रख रखी है। फोटो में रणवीर एक दम
गुजराली लग रहे हैं। बता दें कि रणवीर
इससे पहले बीते दिसंबर की शुरुआत में
फिल्म से अपना पहला लुक शेयर किया था,
जिसमें वह बेहद हैमस नजर आए थे। वहीं एक
दूसरे फोटो में रणवीर के साथ उनकी पूरी टीम नजर
आ रही है।

पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा बचाना है तो यूं ट्रेस कर ट्रांसफर करें फंड

इन-ऑपरेटिव अकाउंट को दूँक करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यह काम घर बैठे ऑनलाइन द्वारा जा सकता है। एक्वाबैल अकाउंट इसमें हो जाने के बाद इसमें जमा राशि ट्रांसफर की जा सकती है या फिर निकाली जा सकती है।

वया होता है इन-ऑपरेटिव अकाउंट? : अगर किसी अकाउंट में तीन साल (36 महीने) तक कुछ जमा नहीं

हिता है तो इसे इन-ऑपरेटिव माना जाता है। 1 अप्रैल 2011 के बाद से सरकार ने ऐसे अकाउंट में जमा राशि पर इंस्ट्रेट देना बंद कर दिया है। एक डेटा के मुताबिक, मार्च 2014 तक श्वक्नह के इन-ऑपरेटिव अकाउंट में 27000 करोड़ रुपये जमा थे। नियम के मुताबिक अगर इन-ऑपरेटिव अकाउंट पर अगर 7 साल तक दावा नहीं किया गया तो सरकार इसे सिनियर सिटिजन के लिए वेलफेयर फंड में डाल देती है।

की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना है। श्वान-अंपरॉयटिव अकाउंट हेल्पडेस्क ऑप्शन को चुनना है। शिकायत बॉक्स में अपनी समस्या के बारे में पूरी जानकारी देनी है। बाद में आपसे निजी जानकारी मांगी जाएगी, मसलन नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्मदिन, पति या पिता का नाम, एलॉन्ग नेमा। इन तथ्यों जानकारी की मदद से आपका अकाउंट आसानी से ट्रैक हो जाएगा।

नई दिल्ली। आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आया है तो उसका आधार कार्ड बनवाने के लिए उसके नामकरण तक का इंतजार क्यों? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का कहना है कि माता-पिता नवजात बच्चे का भी आधार कार्ड (Aadhaar Card) बनवा सकते हैं। यूआईडीएआई के मुताबिक नवजात का आधार बनवाने के लिए उसके थोड़ा बड़ा होने का इंतजार करने की अब जरूरत नहीं है।

A woman in a black jacket and jeans is standing next to a blue recycling bin. She is holding a piece of paper and appears to be about to dispose of it. The bin has a slot for paper and a logo. In the background, there are other recycling bins and a colorful mural on a wall.

ऐसे में आमदनी के प्रमुख स्रोतों के इतर अन्य विकल्पों को ऐसा नहीं रहा।

मुंबई को आशंका है कि 786.7 अरब रुपये के उसने निवेश से होने वाली आमदनी 11व घट जाएगी क्योंकि अगले वित्त वर्ष में बैंक ब्याज दर कम रहेगी। साल 2017 तक मुंबई की आमदनी का एक तिहाई हिस्सा चुंगी (एट्री टैक्स) से मिलता था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद ऐसा नहीं रहा।

बजट में जिस टैक्स सिस्टम की घोषणा की गई का फायदा न मिलने के कारण उसे चुनना पसंद करेंगे। जहाँ सिस्टम चुनेंगे, उन्में ज्यादा टैक्स पाइलिंग की झंझटों से निवेश करते हैं तो बसों के लिए। ऐसे में इनकम टैक्स के तहत मिलने वाले डिड



होने से वे टैक्स सेवर्स में भी निवेश बंद कर नए सिस्टम का रख कर सकते हैं। लेकिन एकसपरर्स का मानना है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखने में ही फायदा है। आइए जानें कौन-कौन से निवेश आपको जारी रखने चाहिए, भले आप नया टैक्स सिस्टम चुनें।

इंश्यादातर लोग
लाइफ और मेडिकल पेंशनर्स भी टैक्स बचाने के लिए खरीदते हैं। प्लैनेस का कहना है कि अब इस सोच में बदलाव आएगा। गेटिंग यू रिच के फंडर व सीओ गैरिथ शाह कहते हैं, 'भले प्रीमियम पर टैक्स ड्यूट ले या न लें, लेकिन सभी के पास लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए।'

नयी दिल्ली । देश की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने छोटें तथा मझौले शहरों के ग्राहकों को लुभाने के लिए सोमवार को अपनी हिंदी वेबसाइट लॉन्च की।

कंपनी ने आज बताया कि उसकी हिंदी वेबसाइट पर उड़ानों, छूट तथा ऑफर के बारे में जानकारी और बुकिंग की सुविधा पूरी तरह हिंदी में होगी। देश में मार्च 2019 में 63.70 करोड़ इंटरनेट इस्तेमालकर्ता थे। इंटरनेट पर हिंदी में कंटेंट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2018-19 में 94 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। इसी को ध्यान में रखते हुये क्षेत्रीय भाषा के ग्राहकों को लुभाने के लिए हिंदी में वेबसाइट शुरू की गयी है।

नई दिल्ली। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 162 अंक लुप्त कर 40979 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 66 अंक फिसलकर 12031 पर बंद हुआ। टीसीएस, भारती एयर टेल, वेदांत लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, लिमिटेड, एम एंड एम लिमिटेड, एस्सीआई और ओएनएसई के शेयर लाल निशान के साथ बंद हुए।



शेयर बाजार लाल निशान के साथ आगे बढ़े। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 41034 के स्तर पर खड़ा कर रहा था तो वहीं निफ्टी भी 26

अंकों के नुकसान के साथ 12071 के स्तर पर। थोड़ी देर बाद ही सेवेरस 41000 के नीचे आ गया। सुहावे सवा दस बजे सेवेरस 250 अंकों के नुकसान के साथ 40,891 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं निफ्टी के 50 में से 41 शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे। निफ्टी 76 अंक लुढ़ककर 12,021 के स्तर पर आ गया। आज आईटी और फर्मा के अतिरिक्त मेटल, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, एम्प्लॉयमेंटीजी, ऑटो, मीडिया समेत सभी सेक्टरर्स लाल निशान पर खुले।

रहा हूँ कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम पदक जीत सकती है। यह अच्छी बात है कि श्यामलाल कॉलेज दिल्ली में हॉकी में चमक रहा है और कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ रवि नारायण कर और असिस्टेंट प्रोफेसर (खेल) वी एस जग्गी हॉकी के साथ-साथ अन्य खेलों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। यह बहुत जरूरी है।

सोप्री ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 मुकाबले में यह आउटबॉल हासिल की। दाएं हाथ की बल्लेबाज सोप्री इसके साथ हार्डन्यूजीलैंड की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गयी हैं जिन्होंने उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी-20 मुकाबले में 65 रनों में 12 चौके और तीन छके लगाकर 105 रन की शतकी पारी खेली जिससे कीवी टीम ने 69 रनों से जीत हासिल की। सोप्री ने ऑकलैंड के खिलाफ वेल्सिंग्टन के लिए खेलते हुए 54 रन बनाए थे।

रहा हूँ कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम पदक जीत सकती है। यह अच्छी बात है कि श्यामलाल कॉलेज दिल्ली में हॉकी में चमक रहा है और कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ रवि नारायण कर और असिस्टेंट प्रोफेसर (खेल) वी एस जग्गी हॉकी के साथ-साथ अन्य खेलों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। यह बहुत जरूरी है।

अयोध्या में भृत्य राम मंदिर के साथ बनेगा कारसेवक स्मारक?

बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट, कारसेवक स्मारक का फैसला स्वागत योग्य

ट्वीट में लिखा- ये शहीद वही रामभक्त हैं, जिन्होंने मंदिर के लिए सब न्योछावर किया

मोदी सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से मंदिर ट्रस्ट का किया है ऐलान

19 फरवरी को दिल्ली में पहली बैठक में मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान संभव

नवप्रदेश संवाददाता
इंदौर। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि

तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया जा चुका है। इसी महिने की ट्रस्ट की पहली बैठक में मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान हो सकता है। इस बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा ट्वीट किया है, जो एक विवाद को जन्म दे सकता है। विजयवर्गीय ने कहा है कि मंदिर के साथ-साथ कारसेवकों की याद में स्मारक बनाने के कदम का वह स्वागत करते हैं। विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए लिखा, स्वागत योग्य कदम!!! अयोध्या में भव्य राम मंदिर के साथ ज्ञात-अज्ञात



कारसेवकों की याद में स्मारक बनाने का फैसला स्वागत योग्य कदम है! ये शहीद वही राम भक्त हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जय जय श्रीराम! सदस्यों का

मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान 19 को?
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' की पहली बैठक 19 फरवरी को दिल्ली में होगी। सूत्रों के मुताबिक, इसमें मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान हो सकता है। रामनवमी (2 अप्रैल) या अक्षय तृतीया (26 अप्रैल) से मंदिर का निर्माण शुरू करने पर सहमति बनने की उम्मीद है।

चुनाव बहुमत के आधार पर होगा। केंद्र सरकार ने 5 फरवरी को ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दी थी। पीएम मोदी ने लोकसभा में इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्रीराम की

तीर्थस्थली पर भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। ट्रस्ट में कुल 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। कार्यशाला में काम कर रहे घनश्याम चतुर्वेदी के मुताबिक मंदिर निर्माण शुरू होने का समय करीब आते देख अब देश के कोने-कोने से आने वाले श्रद्धालु मंदिर कार्यशाला में आ रहे हैं।

कार्यशाला में हो रही पथरों की सफाई

मंदिर निर्माण शुरू होने की खबरों के बीच वीएचपी के श्रीरामजन्म भूमि न्यास कार्यशाला में तराशे गए पथरों की सफाई का काम हो रहा है। वाराणसी से आए कारीगर रामू के मुताबिक पथरों पर लग्नी काई की सफाई चल रही है। इस समय कार्यशाला में तीन कारीगर तराशे गए पथरों की सफाई का काम कर रहे हैं।

न्यूज गैलरी
खिलौनों की आड़ में बेच रहे थे इंपोर्टेड सिगरेट, दो दुकानों पर छापामार कार्रवाई

भोपाल। इंपोर्टेड विदेशी सिगरेट बेचने वाले दो चचेरे भाइयों को क्राइम ब्रांच ने पकड़कर 40 अलग-अलग ब्रांड की सैकड़ों सिगरेट जब्त की हैं। इस छापे की जानकारी पुलिस ने कस्टम विभाग को भी दे दी है। पुलिस को शक है कि कस्टम इयूटी से बचने के लिए आरोपी स्मगलिंग का माल मुंबई के तस्करों से उठाते थे। एसपी निश्चल झारिया के मुताबिक सटीक सूचना के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने लालवानी प्रेस रोड स्थित दो दुकानों पर छाप मारा था। सुपर कलेक्शन और सोनी गिफ्ट सेंटर नाम से संचालित इन दुकानों में खिलौने बेचे जाते हैं। अंदर जाकर देखा तो यहां इंपोर्टेड विदेशी सिगरेट के 40 अलग-अलग ब्रांड रखे मिले। पुलिस ने सैकड़ों सिगरेट जब्त कर लीं। यहां बत्ते पाइप और हड्डा तंबाकू भी पुलिस को मिला। सुपर कलेक्शन गौरव भटेजा का है, जबकि सोनी गिफ्ट सेंटर उसके चचेरे भाई सुनील भटेजा का है। दोनों ग्रीन एकड़, लालघाटी के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे दिल्ली-मुंबई से ये सिगरेट ट्रांसपोर्ट के जरिए भोपाल मंगवाते थे। फिर उन्हें गुमठियों पर बेच दिया जाता था। पुलिस ने इस कार्रवाई की सूचना कस्टम विभाग को भी दे दी है। विदेशी रोड स्थित भानपुर के पास एक हाईवेयर दुकान पर ऊषा और वी-गार्ड कंपनी के नाम पर लोकल सवमर्सिबल पंपसेट बेचे जा रहे थे। इस सूचना के बाद छापामारक क्राइम ब्रांच ने 16 नाग पंपसेट जब्त किए हैं। बगैर बिल दिए इन्हें किसानों को बेचा जाता था। पुलिस ने दुकानदार पंचवटी कॉलोनी, फेस-2 करोंड निवासी 31 वर्षीय मनोज साहू के खिलाफ कोपी राइट एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। ये पंपसेट वह गुजरात से मंगवाकर असल से थोड़ा कम दाम में बेचता था।

इंजीनियरिंग के छात्रों को मिल सकेगी एक साथ दो ब्रांच की डिग्री

भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का मॉडल करिकुलम लागू करने जा रहा है। इसके लागू होने के बाद इंजीनियरिंग के छात्रों को एक साथ दो ब्रांच की डिग्री मिल सकेगी। आरजीपीवी से मिलने वाली डिग्री पर ही छात्रों द्वारा किए गए दोनों ब्रांच के नाम लिखे होंगे। एक ब्रांच नियमित के तौर पर लिखी जाएगी। जबकि एक विशेषज्ञता के तौर पर लिखी जाएगी। इससे छात्रों के लिए सीधे तौर पर रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। दरअसल, एआईसीटीई ने मॉडल करिकुलम तैयार किया था। इसके तहत छात्र अपनी मूल ब्रांच के साथ एक और ब्रांच को पढ़कर उसमें डिग्री हासिल कर सकेगा। छात्रों को मूल ब्रांच में 160 क्रेडिट हासिल करने होंगे। ऐसा करने पर वो माइनर इंजीनियरिंग करने के लिए पात्र हो जाएंगे। इसके बाद ऑप्शनल के तौर पर चयन करने वाली ब्रांच में 20 क्रेडिट हासिल करने होंगे। छात्र को जब डिग्री दी जाएगी तो उसमें दोनों ब्रांच का जिक्र किया जाएगा।अभी आरजीपीवी ने ओपन इलेक्टिव इंजीनियरिंग की शुरुआत कर दी है। इसके तहत 13 ब्रांच को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। छात्र अपने ग्रुप की ब्रांच के साथ ही उसी ग्रुप की एक और ब्रांच को चुन सकता है। छात्रों के लिए यह व्यवस्था पांचवे सेमेस्टर में लागू की गई है। ग्रुप में आपस में जुटी हुई ब्रांच को रखा गया है। आरजीपीवी ने नई व्यवस्था की जानकारी देने के लिए अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी शुरुआत कर दी है। जिससे छात्रों समेत फैकल्टी को नई व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल सके।

मग्न में बनेगी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, जमीन का आरक्षण तय

भोपाल। मध्यप्रदेश में पहली बार अजीम प्रेमजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी खोलेगा। इसके लिए सरकार ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को प्रारंभिक तौर पर 50 एकड़ जमीन देना तय कर लिया है। इसके तहत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने जमीन का लैंडयूज चेंज करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। दरअसल, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने भोपाल में ग्राम कानासैया में 50 एकड़ जमीन को पसंद किया है। इस पर भोपाल संभागायुक्त ने टीएनसीपी को पत्र लिखकर इस जमीन का लैंडयूज शेक्षणित करने की मांग की है। वर्तमान में भोपाल में 2005 का मास्टर प्लान लागू है, जिसमें इस जमीन का उपयोग कृषि के लिए दर्शाया गया है। इस कारण यहां यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए पहले इस जमीन का लैंड-यूज बदलना होगा।

इंदौर की पंचायत को मिलेगा देश का पहला मूक बधिर सरपंच!

डांसरी गांव को कुछ समय पहले ही मिला था ग्राम पंचायत का दर्जा

अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के उम्मीदवार के लिये आरक्षित किया गया है पद

चुनावों में स्थानीय निवासी लालू का निर्विरोध सरपंच निर्वाचित होना लगभग तय

नवप्रदेश संवाददाता

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की एक ग्राम पंचायत को देश का पहला मूक बधिर सरपंच मिलने जा रहा है। राज्य में आगामी दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव में लालू (27) नाम के इस युवक की जीत तय मानी जा रही है। इंदौर शहर से करीब 40



किलोमीटर दूर डांसरी गांव के निवासी हैं। डांसरी गांव को कुछ समय पहले ही ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है। वह इस गांव के इकलौते अनुसूचित जनजाति के वोटर हैं और इस बार इस पंचायत से उनके सरपंच बनने की बात कही जा रही है। करीब 1,000 लोगों की आबादी वाले इस गांव की नवगठित पंचायत के आगामी चुनावों के लिए सरपंच का पद चक्रानुक्रम (रोटेशन)

शौचालय के साथ तस्वीर खिंच गई और लाभार्थियों को पता भी नहीं 540 करोड़ रुपये का स्वच्छ भारत घोटाला

मध्य प्रदेश के बेतुल में स्वच्छ भारत योजना के तहत 540 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया

इस लागत से बनाए जाने वाले 4.5 लाख से भी अधिक शौचालय सिर्फ कागजों तक ही सीमित है

सरकार ने आरोपियों से प्रत्येक शौचालय में खर्च होने वाले पैसे जब्त करने के आदेश दिए

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत योजना के तहत 540 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि इस लागत से बनाए जाने वाले 4.5 लाख से भी अधिक शौचालय सिर्फ कागजों तक ही सीमित



है, इनका जमीन पर निर्माण नहीं हुआ। जबकि प्रशासन का दावा था कि उसके पास प्रत्येक शौचालय का जीपीएस टैग फोटो भी है। अब सरकार ने आरोपियों से प्रत्येक शौचालय में खर्च होने वाले पैसे जब्त करने के आदेश दिए हैं। इस शौचालयों का निर्माण 2012 से 2018 के बीच होना था लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि ये शौचालय सिर्फ कागज तक ही सीमित हैं। अब अधिकारियों को भी अहसास होने लगा है कि स्वच्छ टॉइलेट निर्माण के सबूत

के रूप में जो तस्वीरें ली गई थीं वह किसी और जगह की थीं। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब बेतुल के लकड़जाम पंचायत के कुछ ग्रामीणों ने अधिकारियों के पास जाकर शिकायत की थी। चार स्वच्छ लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनके नाम से शौचालयों का निर्माण हो चुका है। लेकिन सरकारी दस्तावेजों में न सिर्फ यह कहा गया है कि उनके घरों में शौचालय हैं बल्कि टॉइलेट्स के सामने उनकी तस्वीरें भी हैं। जांच में खुलासा हुआ कि सभी तस्वीरें पड़ोस के घर की थीं। बेतुल पंचायत के सीईओ एमएल त्यागी ने बताया, इन शौचालय और दूसरी विसंगतियों के लिए आरोपी से 7 लाख रुपये की वसूली की जाएगी। आरोपियों ने वसूली आदेश के खिलाफ अपील की, लेकिन जुर्माना बरकरार रखा गया

बीजेपी का सीएम कमलनाथ पर हमला- बताया 15 प्रतिशत वाली सरकार

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के पीएम मोदी पर दिये बयान पर बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि खुद कमलनाथ बड़े कलाकार हैं, सब जानते हैं कि इनकी बस 15 प्रतिशत वाली सरकार है। दूरअसल, सागर की एक सभा में कमलनाथ ने पीएम मोदी को लेकर कहा था कि मुंह पलाने और देश पलाने में बहुत अंतर होता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा था, मोदी जी, प्लान मोड़ने के लिए कभी राष्ट्रवाद की बात करेंगे कभी अफिरतान की बात करेंगे लेकिन नौजवालों और किसानों की बात नहीं करेंगे।

सीहोर में दबंगों ने विधवा मां और बेटी की चोटी पकड़कर लात-मुक्के मारे

मां-बेटी के साथ मारपीट की वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई

पुलिस ने आरोपी धर्मेन्द्र पाटीदार और तीन अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया

सीहोर। यहां एक विधवा महिला और उसकी बेटी के साथ शहर के तीन गुंडों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की। दोनों की



चोटी पकड़कर लात और मुक्के भी मारे गए। घटना इंग्लिशपुरा क्षेत्र में रविवार शाम की है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। लेकिन, एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़ित मां-बेटी ने मारपीट के फुटेज पुलिस को दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, महिला के पति की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। वह अपनी बेटी के साथ एक मकान में अकेली रहती हैं। धर्मेन्द्र पाटीदार नाम का रसूखदार महिला के मकान को अपना बताकर खाली करने को कह रहा है। धर्मेन्द्र महिला के पति का दोस्त था। बताया जा रहा है कि महिला के पति और धर्मेन्द्र के बीच रुपयों का लेनदेन रहता था। रविवार शाम धर्मेन्द्र अपने तीन दोस्तों के साथ महिला के घर पहुंचा।

और बढ़ गया विवाद, शबिस्ता बोलीं-मेयर के खिलाफ दर्ज कराऊंगी मानहानि का केस

शबिस्ता ने कहा कि कब्रिस्तान और वक्फ की जमीन पर एप्रोच रोड का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा

भोपाल। महापौर आलोक शर्मा और कांग्रेस पार्षद शबिस्ता जकी के बीच चल रहा विवाद बढ़ता जा रहा है। शबिस्ता जकी ने रविवार को आर्च ब्रिज पर प्रदर्शन किया और दावा किया कि महापौर जिस जमीन पर अवैध कब्जे की बात कह रहे हैं वह उन्हें पूर्व से आवंटित है। उन्होंने कहा कि वे

महापौर के खिलाफ मानहानि का केस लगाएंगी। शबिस्ता ने कहा कि कब्रिस्तान और वक्फ की जमीन पर एप्रोच रोड का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। उधर, रानी कमलापति की प्रतिमा के अनावरण के लिए महापौर आलोक शर्मा द्वारा दी गई 72 घंटे की चेतावनी की मियाद सोमवार को पूरी हो रही है। महापौर ने कहा कि वे प्रोटोकॉल के अनुसार प्रतिमा के लोकार्पण के लिए चर्चा करेंगे।

बिना वजह सिजेरियन या दूसरे ऑपरेशन किए तो सील हो सकता है नर्सिंग होम!

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। कमलनाथ सरकार माफिया पर नकेल कस रही है। अभी तक भू माफिया और कुछ ज्यादा ही मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सरकार का मिशन प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने का है। इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों के माफिया पर सरकार अपनी नजर रख रही है। बात अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की करें तो पहले तो सरकार ने

ऑपरेशन हो रहे हैं। सरकार उन नर्सिंग होम्स की कुंडली तैयार कर रही है जहां नकेल कस रही है। अभी तक भू माफिया और कुछ ज्यादा ही मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सरकार का मिशन प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने का है। इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों के माफिया पर सरकार अपनी नजर रख रही है। बात अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की करें तो पहले तो सरकार ने



खाद्य पदार्थों के मिलावट खोरों पर लगाम कसी।फिर इग माफिया पर शिकंजा कसा।नकली कास्मेटिक के सप्लायर्स पर भी सरकार ने कानूनी कार्रवाई की। और अब स्वास्थ्य विभाग की नजर उन हेल्थ लुटेरों पर है जो मरीजों से लंबा-चौड़ा बिल वसूलने के लिए ज़रूरत ना होने पर भी उनका

ऑपरेशन कर देते हैं। सबसे ज्यादा शिकायत प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स से मिल रही है। इस लिए स्वास्थ्य विभाग इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। जब ऑपरेशनों के डाटा को चेक किया तो ये बात सामने आई कि प्राइवेट नर्सिंग होम्स में डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा सिजेरियन ऑपरेशन किए जा रहे हैं।ये सिलसिला बरसों से चल रहा है।